स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया-प्रशांत साझीदारी

परिचय

स्वच्छ विकास और जलवायु के मुद्दे पर एशिया- प्रशांत के सात बड़े देश -ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका - एक मंच पर आ गए हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था , जनसंख्या और ऊर्जा इस्तेमाल के आधे से भी अधिक पर इनकी हिस्सेदारी है। बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों और वायु प्रदूषण , ऊर्जा सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन जैसे संबद्ध मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए ये आपस में सहयोग कर रहे हैं।

सरकारी और निजी क्षेत्रों के नए व सामूहिक प्रयास के तौर पर एशिया- प्रशांत सीझीदारी का गठन आर्थिक विकास बढ़ाने, निर्धनता घटाने और स्वच्छतम , ज्यादा कुशल तकनीकों के विकास और इनकी तैनाती के उद्देश्य से हुआ। यह सीझीदारी मौजूदा दोपक्षीय और बहुपक्षीय पहल की बुनियाद पर खड़ी व दृढ़ है, और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर ढांचागत योगदान करती हुई क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करती है।

साझीदारी के बिंदु

साझीदारी के तहत कार्य योजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के लिए आठ सरकारी और निजी कार्य बल गठित किए गए हैं। ये कार्य बल पांच ऊर्जा गहन क्षेत्र- एल्युमीनियम, निर्माण और उपकरण, सीमेंट, कोयला खनन और इस्पात- व ऊर्जा आपूर्ति करने वाले तीन क्षेत्र -स्वच्छतम जीवाश्म ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और वितरित उत्पादन, और विद्युत उत्पाद व संचरण- पर केंद्रित हैं।

साझीदारी की गतिविधियां

एशिया-प्रशांत साझीदारी के कार्यों में विभिन्न तरह की गतिविधियां शामिल हैं। साझीदारी परियोजनाओं का शुरुआती हिस्सा क्षेत्रीय आकलन, क्षमता निर्माण, बेहतर प्रयोगों की पहचान, और तकनीकी शोध और प्रदर्शन पर जोर देता है। साझीदारी काम के कुछ उदाहरण इस तरह हैं:

* एलुमिनियम उत्पादन में बॉक्साइट अवशिष्ट प्रबंधन।
* ऊर्जा कुशल प्रकाश के मानकीकरण में सहयोग।
* सीमेंट भट्ठियों के कूड़े का ईंधन में रूपांतरण।
* कोयले से चलनेवाली विद्युत इकाइयों में कार्बन प्राप्ति तकनीक में सुधार।
* कोयला खदान स्वास्थ्य और सुरक्षा रणनीतियों का विकास।
* विद्युत उत्पादन में बेहतर प्रयोगों का आदान-प्रदान।
* सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, और
* स्वच्छतम इस्पात तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना।

सांगठनिक ढांचा

नीति और कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) साझीदारी के काम का निरीक्षण करती है, कार्य बल को दिशा- निर्देश देती है और नियत समय पर उनके काम- काज की समीक्षा करती है। प्रशासनिक सहायता समूह , जिसकी मेजबानी फिलहाल अमेरिका के पास है, व्यापक रूप से पीआईसी और साझीदारी का सहयोग करता है। कार्य बल का नेतृत्व सभापति और उप- सभापति करते हैं, जो सरकारी-निजी क्षेत्र के सहयोग का सर्वेक्षण करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया • कनाडा • चीन • भारत • जापान • कोरिया • संयुक्त राज्य अमेरिका

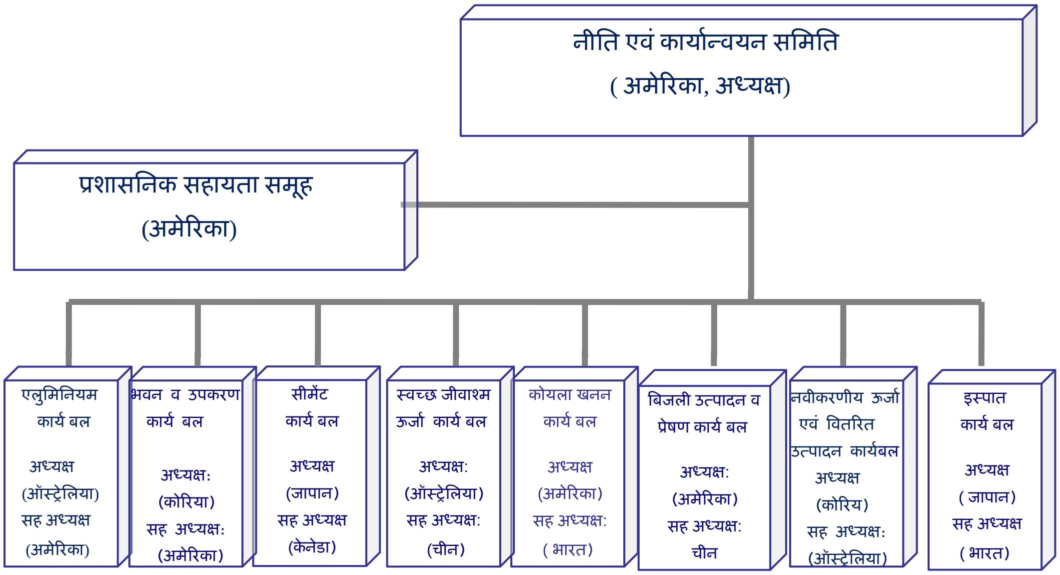

पृष्ठभूमि

एशिया-प्रशांत साझीदारी की घोषणा जुलाई , 2005 में लाओस के विएनटाइन में ३८वें आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जनवरी, 2006 में मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई। सिडनी में मौजूद मंत्रिगण एक घोषणापत्र , सरकारी विज्ञप्ति और कार्य योजना पर भी सहमत हुए।

अप्रैल, 2006 में नीति और क्रियान्वयन समिति (पीआईसी) की कार्य बल के साथ अमेरिका के बर्कले में बैठक हुई। फिर कार्य बल ने संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी प्राथमिकताओं और विकासशील कार्य योजनाओं को चिह्नित करना शुरू किया। अक्तूबर , 2006 में कोरिया के जेजु में साझेदारों ने आठ कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया, जिनमें करीब सौ विभिन्न परियोजनाएं और गतिविधियां जुड़ी हुई थीं।

कार्य बलों ने तब से अपने काम काज का कार्यान्वयन चरण शुरू किया और वे लगातार बैठक करने लगे। जुलाई, 2007 में जापान के टोक्यो में पीआईसी की बैठक में कार्य बल ने अपने काम की रिपोर्ट दी, और पीआईसी ने नई परियोजनाओं को अनुमोदित करने के साथ दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की शुरुआत की।

अक्तूबर, 2007 में नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय बैठक में मत्रियों ने सातवें साझेदार के तौर पर कनाडा का स्वागत किया, कार्य योजनाओं और इनसे संबंधित 100 से अधिक परियोजनाओं , साथ ही साथ 18 मुख्य परियोजनाओं की पहचान की , और एशिया-प्रशांत ऊर्जा तकनीकी सहयोग केंद्र की शुरुआत की घोषणा की।

शंघाई, चीन में अक्तूबर 2009 की मंत्री स्तरीय बैठक में मंत्रियों ने नई दिल्ली में हुई मंत्री स्तरीय बैठक के बाद से साझेदारी की उपलब्धियों पर विचार किया, और एपीपी की ध्वजपोत परियोजनाओं की प्रगति का विश्लेषण और मूल्यांकन करने वाली रिपोर्ट के परिणाम प्राप्त किये. मंत्री स्तरीय बैठक के संयोजन में एपीपी के पीआईसी सदस्यों ने भी बैठक की और एपीपी के भावी कार्य पर विचार किया तथा एक नई परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया.

साझीदारी, इसकी आनेवाली घटनाओं, और इनसे जुड़ने के बारे में और जानकारी के लिए कृपया www.asiapacificpartnership.org पर देखें या Administrative Support Group, APP_ASG@state.gov. पर संपर्क करें